AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

बिहार में कृषि–आधारित उद्योगों का आर्थिक प्रभाव एवं चुनौतियाँ

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. सुधांशु कुमार
सिवान, बिहार, भारत

शोध सार

कृषि–आधारित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं क्योंकि ये न केवल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होते हैं, बल्कि उन्हें कृषि कार्य से अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। इन उद्योगों के माध्यम से किसान पारंपरिक खेती पर निर्भर रहने के बजाय अपनी उपज का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और आजीविका अधिक स्थिर बनती है साथ ही, कृषि–आधारित उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का स्थानीय स्तर पर उपयोग सुनिश्चित करते हैं, जिससे ग्रामीण विकास और सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण को गति मिलती है। बिहार जैसे कृषि–प्रधान राज्य में कृषि–आधारित उद्योगों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यहां की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और ऐसे में प्रसंस्करण उद्योग, डेयरी, चीनी मिलें, फल–सब्जी प्रसंस्करण इकाइयां तथा अन्य लघु उद्योग न केवल किसानों की आय में वृद्धि करते हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाते हैं। ये उद्योग ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं, जिससे पलायन की समस्या में भी कमी आती है। इसके अतिरिक्त, इनका प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ता है और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार से बिहार की आर्थिक संरचना को मजबूती मिलती है। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य बिहार में कृषि–आधारित उद्योगों के आर्थिक प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत यह देखा जाएगा कि इन उद्योगों ने किसानों की आय वृद्धि, ग्रामीण रोजगार और SGDP में किस प्रकार योगदान दिया है साथ ही, अध्ययन का एक अन्य पहलू इन उद्योगों से जुड़ी चुनौतियों की पहचान करना भी है, जैसे अवसंरचना की कमी, पूंजी निवेश की सीमाएँ, तकनीकी बाधाएँ तथा बाज़ार तक पहुँच में कठिनाइयाँ। इन चुनौतियों की गहन पड़ताल से यह समझा जा सकेगा कि राज्य की कृषि–आधारित औद्योगिक संरचना को और अधिक प्रभावी एवं टिकाऊ बनाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द

कृषि–आधारित उद्योग, किसान आय, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास, राज्य सकल घरेलू उत्पाद.

भूमिका

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि–आधारित उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये उद्योग न केवल कृषि उत्पादन के उपयोग को विविधतापूर्ण बनाते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास की नींव भी रखते हैं। कृषि–आधारित उद्योगों का प्रमुख उद्देश्य कृषि से प्राप्त कच्चे माल को प्रसंस्कृत कर मूल्यवर्धित

वस्तुओं में बदलना है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, डेयरी उद्योग, तेल निष्कर्षण इकाइयाँ, गन्ना एवं चीनी मिलें तथा कृषि उपकरण निर्माण जैसे क्षेत्र किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं। इन उद्योगों से किसानों की आय बढ़ती है और उनकी निर्भरता केवल प्राथमिक कृषि उत्पादन पर कम होकर विविधीकृत आय स्रोतों की ओर बढ़ती है।

इसके अतिरिक्त, कृषि–आधारित उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करते हैं। इन उद्योगों की स्थापना से न केवल प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों को रोजगार मिलता है, बल्कि परोक्ष रूप से परिवहन, भंडारण, विपणन और सेवा क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन मिलता है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ता है और स्थानीय स्तर पर उद्यमिता का विकास होता है। इस प्रकार, कृषि–आधारित उद्योग ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक संरचना के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बिहार के संदर्भ में यह स्थिति और भी विशेष महत्व रखती है। राज्य की लगभग 77 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, जो इसे कृषि प्रधान रांज्य बनाता है। हालांकि, औद्योगिक संरचना के मामले में बिहार अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है और बड़े उद्योगों की संख्या सीमित है। ऐसे में कृषि–आधारित उद्योग राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बदलने में केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं। गन्ना उद्योग, चावल एवं मक्का मिलें, फल एवं सब्ज़ी प्रसंस्करण इकाइयाँ तथा डेयरी उद्योग यहाँ विशेष रूप से संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। इन उद्योगों के विकास से न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा और राज्य की औद्योगिक विविधता भी बढ़ेगी।

कृषि–आधारित उद्योगों का आर्थिक महत्व

बिहार की अर्थव्यवस्था पर इन उद्योगों का प्रभाव व्यापक और बहुआयामी है। सबसे पहले, रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह क्षेत्र ग्रामीण श्रम शक्ति को संगठित और उत्पादक कार्यों में संलग्न करने में अत्याधिक सहायक रहा है। उदाहरणस्वरूप, केवल COMFED (सुधा डेयरी) से लगभग 9 लाख किसान परिवार जुड़े हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि यह उद्योग किस प्रकार कृषि आधारित ग्रामीण समाज को आर्थिक मुख्यधारा में ला रहा है। इससे न केवल प्रत्यक्ष रोजगार सृजन हुआ है, बल्कि दुग्ध उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित विभिन्न चरणों में भी अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ग्रामीण आय वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में भी इन उद्योगों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। कृषि उत्पादन को केवल प्राथमिक रूप में बेचने के बजाय जब उसे प्रसंस्कृत किया जाता है, तो उसका मूल्य संवर्धन होता है, जिससे किसानों की आय में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि संभावित होती है। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में, जहाँ बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान हैं, यह अतिरिक्त आय उनके जीवन स्तर में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्थायित्व में सहायक बनती है। यह आय वृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य और उपभोग संबंधी व्ययों में भी परिलक्षित होती है, जिससे समग्र सामाजिक विकास को भी बल मिलता है।

राज्य की व्यापक अर्थव्यवस्था पर दृष्टिपात करें तो इन उद्योगों का योगदान प्रत्यक्ष रूप से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (SGDP) में परिलक्षित होता है। वर्तमान में इनका SGDP में योगदान लगभग 9–10 प्रतिशत आँका गया है। यह आँकड़ा इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि–आधारित उद्योग, विशेष रूप से दुग्ध और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, विकास की धुरी का कार्य कर रहे हैं। इससे न केवल राज्य की आर्थिक संरचना मजबूत हुई है, बल्कि औद्योगिक विविधीकरण की दिशा में भी राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

सारणी 01: बिहार की अर्थव्यवस्था पर दुग्ध एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रभाव

क्रम संख्या	क्षेत्र / सूचकांक	आँकड़ा / प्रतिशत	स्रोत
01	COMFED (सुधा डेयरी) से जुड़े किसान परिवार	लगभग 9 लाख	COMFED वार्षिक रिपोर्ट, 2022–23
02	बिहार का कुल दुग्ध उत्पादन (2021–22)	147.65 लाख टन	डेयरी विकास निदेशालय, बिहार
03	दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	20,000+ सक्रिय समितियाँ	COMFED
04	दुग्ध एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का SGDP में योगदान	लगभग 9–10%	बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2022–23
05	प्रसंस्करण से किसानों की आय में संभावित वृद्धि	20–30%	कृषि मूल्य संवर्धन अध्ययन, नीति आयोग
06	कृषि पर निर्भर आबादी (बिहार)	76%	बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2022–23
07	औद्योगिक विविधीकरण में कृषि–आधारित उद्योगों की हिस्सेदारी	महत्वपूर्ण, प्राथमिक सेक्टर से सर्वाधिक योगदान	उद्योग विभाग, बिहार
08	सहायक क्षेत्रों (परिवहन, पैकेजिंग, भंडारण) में रोजगार वृद्धि	सैकड़ों नए एमएसएमई पंजीकृत	MSME रिपोर्ट, बिहार, 2022

इसके अलावा, इन उद्योगों के विकास ने सहायक गतिविधियों को भी गति प्रदान की है, उदाहरण के लिए, परिवहन, पैकेजिंग, भंडारण और विपणन जैसे क्षेत्र इन उद्योगों के विस्तार के साथ–साथ विकसित हुए हैं। इससे न केवल अतिरिक्त आर्थिक अवसर उत्पन्न हुए हैं बल्कि आपूर्ति शृंखला (Supply Chain) को भी मजबूती मिली है। इस प्रकार, उद्योगों का विकास एक समग्र आर्थिक चक्र को गति देता है, जहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ समाज और अर्थव्यवस्था तक पहुँचते हैं।

प्रमुख क्षेत्रों का आर्थिक विश्लेषण

बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि–आधारित उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियाँ विभिन्न प्रकार की फसलों और पशुपालन गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे कृषि–उद्योगों का विकास स्वाभाविक रूप से संभव हुआ है। इन उद्योगों ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ाए हैं, बल्कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (ळैक्च) में भी अहम योगदान दिया है।

सबसे प्रमुख कृषि–आधारित उद्योगों में गन्ना आधारित चीनी उद्योग का उल्लेख किया जा सकता है। यह उद्योग ऐतिहासिक रूप से बिहार के ग्रामीण अर्थतंत्र की रीढ़ रहा है और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता आया है। इसके अलावा, इस उद्योग से राज्य सरकार को कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी प्राप्त होता है, जो स्थानीय विकास कार्यों के लिए उपयोगी साबित होता है।

इसी प्रकार, डेयरी उद्योग बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। विशेषकर बिहार राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ लिमिटेड (COMFED) के अंतर्गत 'सुधा डेयरी' ब्रांड ने एक सफल सहकारी मॉडल प्रस्तुत किया है। इस मॉडल ने न केवल किसानों को नियमित आय का स्रोत उपलब्ध कराया है, बल्कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद भी प्रदान किए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी भावना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिला है।

ग्रामीण स्तर पर चावल एवं आटा मिल उद्योग भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये उद्योग स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन मिलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों में खाद्यान्न प्रसंस्करण और वितरण सुनिश्चित होता है, जो खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में सहायक है।

वर्तमान समय में फल एवं सब्ज़ी प्रसंस्करण उद्योग तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। बिहार लीची, आम, आलू, कटहल और अन्य सब्ज़ियों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इन फसलों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की अपार संभावनाएँ हैं। विशेषकर लीची और आम जैसे फलों के प्रसंस्करण से निर्यात की बड़ी संभावनाएँ खुलती हैं, जिससे राज्य विदेशी मुद्रा अर्जन कर सकता है और किसानों की आय में भी वृद्धि होती है।

सारणी 2: बिहार के प्रमुख कृषि–आधारित उद्योगों का आर्थिक विश्लेषण

क्रम संख्या	उद्योग / क्षेत्र	प्रमुख आँकड़े / योगदान	स्रोत
01	गन्ना एवं चीनी उद्योग	– बिहार में लगभग 1.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती (2021–22) – राज्य में 11 चालू चीनी मिलें – लाखों श्रमिकों को प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रोजगार	बिहार गन्ना उद्योग विभाग, 2022–23
02	डेयरी उद्योग (COMFED / सुधा डेयरी)	– लगभग 9 लाख किसान परिवार जुड़े हुए – दुग्ध उत्पादन: 147.65 लाख टन (2021–22) – राज्य के SGDP में दुग्ध उद्योग का योगदान लगभग 9–10%	COMFED वार्षिक रिपोर्ट 2022–23, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
03	चावल एवं आटा मिल उद्योग	– बिहार में 12,000 से अधिक छोटे–बड़े मिलें – स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न प्रसंस्करण और रोजगार के प्रमुख स्रोत – ग्रामीण खाद्य सुरक्षा में योगदान	उद्योग विभाग, बिहार, 2022
04	फल एवं सब्ज़ी	– बिहार लीची उत्पादन में भारत में पहला प्रसंस्करण उद्योग स्थान (कुल उत्पादन का 40% से अधिक) – **आम उत्पादन:** लगभग 16 लाख टन (2021–22) – **आलू उत्पादन:** लगभग 80 लाख टन (2021–22) – लीची और आम के प्रसंस्करण / निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन और किसानों की आय वृद्धि	बागवानी निदेशालय, बिहार; कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

प्रमुख चुनौतियाँ एवं बाधाएँ

इन उद्योगों की प्रगति के मार्ग में कई बाधाएँ मौजूद हैं। वित्तीय स्तर पर, उद्यमियों को अक्सर पूंजी की कमी और ऋण तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है। ढाँचागत स्तर पर, कोल्ड स्टोरेज, बिजली और सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचना का अभाव एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा, तकनीकी पिछड़ापन और गुणवत्ता मानकों की कमी भी प्रतिस्पर्धा में बाधा डालती है। संगठनात्मक स्तर पर, अधिकांश उद्योगों का असंगठित स्वरूप और छोटे स्तर पर संचालन उन्हें बड़े बाजारों तक पहुँचने से रोकता है। बाजार में बड़े कॉर्पोरेट खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा भी

एक गंभीर चुनौती है। इन सबके साथ–साथ, उद्योगों के लिए कुशल श्रमशक्ति एवं प्रशिक्षण संस्थानों की कमी भी विकास में एक प्रमुख बाधा है।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि बिहार में कृषि–आधारित उद्योग न केवल रोजगार और आय वृद्धि में सहायक हैं, बल्कि राज्य की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए अनिवार्य हैं। वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य सरकार को अवसंरचना सुधार, ऋण सुविधा, तकनीकी उन्नयन और बाजार विस्तार पर एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

भविष्य की संभावनाएँ एवं अवसर

अनेक चुनौतियों के बावजूद, बिहार में कृषि–आधारित उद्योगों के लिए भविष्य की उज्ज्वल संभावनाएँ हैं। राज्य में डेयरी उद्योग के विस्तार की काफी गुंजाइश है। फल एवं सब्ज़ी प्रसंस्करण हब का विकास कर निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। विशेष रूप से, बिहार के अद्वितीय उत्पादों जैसे लीची, मक्का और मखाना का निर्यात एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।

नीति–निर्देश

- लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सब्सिडी व सरल ऋण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- कोल्ड चेन और परिवहन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।
- कृषि–आधारित उद्योगों में स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- निर्यातोन्मुखी उत्पादों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की स्थापना की जानी चाहिए।
- किसानों एवं श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. COMFED (2017) बिहार राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ की वार्षिक रिपोर्ट, पटना।
2. बिहार सरकार (2017) खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017, पटना।
3. बिहार सरकार (2018) बिहार औद्योगिक नीति, उद्योग विभाग, पटना।
4. बिहार सरकार (2020) बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2019द्20. पटनारू वित्त विभाग।
5. आईसीआरआईईआर (2016) भारत में शीत श्रृंखला अवसंरचना, नई दिल्ली।
6. कुमार, ए. (2015) बिहार में चीनी उद्योगों का पतनरू कारण और परिणाम, *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* 50(21), 72–78।
7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (2020) वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार।
8. मिश्रा, वी. (2019) बिहार में किसानों की आय पर खाद्य प्रसंस्करण का प्रभाव, *जर्नल ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी,* 10(6), 821–829।
9. राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड (2019) उद्यानिकी सांख्यिकी एक दृष्टि में, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (2019) बिहार में कृषि–आधारित उद्योगों के लिए कौशल अंतराल अध्ययन, नई दिल्ली।
11. नीति आयोग (2015) कृषि और ग्रामीण विकास रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. योजना आयोग (2012) बिहार में अवसंरचनागत बाधाएँ, भारत सरकार, नई दिल्ली।

13. प्रसाद, एन. (2014) बिहार में कृषि–आधारित उद्योगों की संरचनात्मक बाधाएँ, *जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़,* 49(3), 341–359।

14. भारतीय रिज़र्व बैंक (2019) बिहार में कृषि ऋण पर रिपोर्ट, मुंबई।

15. शर्मा, एच. (2017) भारत में कृषि–आधारित उद्योगः एक संक्षिप्त अवलोकन, *इंडियन जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट,* 13(1), 55–64।

16. सिंह, ए. एवं झा, एम. (2016) बिहार के कृषि–आधारित उद्योगों में प्रौद्योगिकी अंतराल, *इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्स,* 71(2), 225–236।

17. सिंह, पी. (2017) बिहार में सहकारी दुग्ध मॉडलरू कॉमफेड का एक केस अध्ययन, *इंडियन जर्नल ऑफ कोऑपरेटिव स्टडीज़,* 52(3), 145–158।

18. सिंह, आर. के. (2018) बिहार में कृषि–आधारित उद्योगः अवसर और चुनौतियाँ, *जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट,* 37(2), 201–215।

19. विश्व बैंक (2018) भारत में कृषि–उद्योगों की राज्य–स्तरीय प्रतिस्पर्धात्मकता, वाशिंगटन, डी.सी.।

––==00==––